साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 114 | जौनपुर, शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा

हनुमान मंदिर अक्षयवट और संगम पर पहुचे

प्रयागराज ,(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर बृहस्पतिवार को फिर प्रयागराज पहुंचे। संगम पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री के सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके पूर्व वह मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल का भी जायजा लिया। सीएम ने केंद्रीय हॉस्पिटल की तैयारियों को सराहा। आईसीयू वार्ड के एआई सिस्टम को भी देखा। निरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा समय आईसीयू वार्ड में ही बिताया। योगी ने वेंटिलेशन हॉस्पिटल में वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री गंगा रिवर फ्रंट रोड समेत महाकुंभ के कई अन्य निर्माण कार्यों का

निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संगमनगरी पहुंच रहे हैं। मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। साथ ही सात हजार करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री अभी सात दिसंबर को आए थे। इससे पहले 27 नवंबर को भी वह आए थे। इस तरह से 15 दिनों में यह उनका तीसरा दौरा है। मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर दिन में 12 बजे पुलिस लाइन मैदान पर उतरा। यहां से वह महाकुंभ क्षेत्र के परेड मैदान में बने केंद्रीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। फिर किला घाट और वहां बनी जेटी का निरीक्षण किया। इसके बाद संगम नोज पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। योगी ने अक्षयवट, हनुमान मंदिर, सरस्वती कूप का भी निरीक्षण किया। प्रयागराज दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। सभा स्थल के साथ ही संगम पर बने जेटी, पूजन स्थल के साथ ही सरस्वती कूप, किला घाट, गंगा घाट, अक्षयवट और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का जायजा लेते हुए दर्शन पूजन भी किया। मेला कार्यालय पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ दोपहर का भोजन किया और पीएम मोदी के दौरान की गई व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। इसके बाद योगी ने सलोरी में एसटीपी का निरीक्षण किया। यहां पर काले पानी को एसटीपी के जरिए साफ करके दिखाया गया, जिसकी सीएम ने तारीफ की और संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के समय सीएम की गाड़ी में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद रहे। सीएम योगी आगे वाली सीट पर चालक के बगल बैठे रहे, जबकि पीछे वाली सीट पर केशव, नंदी और स्वतंत्रदेव बैठे रहे। संगम और हनुमान मंदिर कॉरिडोर के साथ एसटीपी और रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूंसी में छतनाग घाट पर पहुंचे। यहां की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

पीएम मोदी देंगे 7000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

प्रयागराज ,(संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर बृहस्पतिवार को फिर आएंगे। वह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के हर आयोजन स्थल का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री गंगा रिवर फ्रंट रोड समेत महाकुंभ के कई अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शहर में होंगे। प्रधानमंत्री गंगापूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। साथ ही सात हजार करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के साथ शुक्रवार तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही, एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भी वह प्रयागराज आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी सात दिसंबर को आए थे। इससे पहले 27 नवंबर को भी वह आए थे। इस तरह से 15 दिनों में यह उनका तीसरा दौरा होगा। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दिन में 12 बजे पुलिस लाइन मैदान पर

उतरेगा। पुलिस लाइन से महाकुंभ क्षेत्र के परेड मैदान में बने केंद्रीय अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। फिर किला घाट एवं वहां बने जेटी का निरीक्षण करेंगे। फिर संगम नोज जाएंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही तैयारियों को देखेंगे। संगम नोज पर ही प्रधानमंत्री संतों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री इसकी तैयारियों को भी देखेंगे। इसी क्रम में वह अक्षयवट, हनुमान मंदिर, सरस्वती कूप का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह परेड स्थित मेला प्रशासन के अस्थाई कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों संग वार्ता कर प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद सलोरी स्थित एसटीपी तथा जियो ट्यूब विधि से शोधन कार्य, सेक्टर 20 में स्थापित अखाड़ों की बसावट, झूंसी में गंगा रिवर फ्रंट तथा छतनाग घाट का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दिन में करीब तीन बजे वह पुलिस लाइन आएंगे और हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की

नई दिल्ली,(एजेंसी)।एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।प्रफुल्ल पटेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं। प्रफुल्ल पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलना सौभाग्य की बात है, साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील तटकरे और राज्यसभा सांसद श्रीमती सुनेत्रा पवार भी मौजूद थीं। महाराष्ट्र के विकास के लिए विचारों का शानदार आदान–प्रदान हुआ। महाराष्ट्र चुनावों में महायुति की भारी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद से कहीं ज़्यादा सीटें मिली हैं। टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा श्एक है तो सुरक्षित हैश राज्य में ष्जादूष् की तरह काम करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीतने पर फडणवीस ने कहा, ष्मुझे पता था कि वे (महायुति) चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मुझे पता था कि हम (भाजपा) 132 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन यह गलत है कि उन्हें नहीं पता था कि हम बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रहे हैं। हमें अपनी अपेक्षा से अधिक संख्या मिली।ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की।मील का पत्थर साबित किया, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी क्रमशः 57 और 41 सीटों के साथ उल्लेखनीय लाभ कमाया। उल्लेखनीय रूप से, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनावों में बड़ा झटका लगा, जिसमें कांग्रेस ने 288 विधानसभा सीटों में से केवल 16 सीटें जीतीं।

संविधान पर बहस के लिए अपने लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया

नई दिल्ली,(एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों (सांसदों) के लिए श तीन लाइन व्हिप नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 13 और 14 दिसंबर को भारत के संविधान पर निर्धारित बहस के दौरान निचले सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। भाजपा के आधिकारिक बयान में कहा गया है, ष्लोकसभा में सभी भाजपा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार, 13 दिसंबर और शनिवार, 14 दिसंबर 2024 को लोकसभा में चर्चा की जाएगी। इसलिए, लोकसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे दोनों दिन यानी शुक्रवार, 13 दिसंबर और शनिवार, 1 दिसंबर 2024 को सदन में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।ष सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 14 दिसंबर को लोकसभा में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर बहस का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे। इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले और 13 दिसंबर को सहमति के अनुसार संविधान पर बहस हो। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ष्मैंने अध्यक्ष के साथ बैठक की। मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे... हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। चाहे वे मेरे बारे में कुछ भी कहें, हम चाहते हैं कि 90 दिन का समय 13 दिसंबर को बहस हो।

अंत में, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वे हम पर आरोप लगाते रहेंगे लेकिन सदन चलना चाहिए।ष शीतकालीन संसद का पहला सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसमें व्यवधानों के कारण दोनों सदनों को काफी पहले स्थगित कर दिया गया था। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ आरोपों पर चर्चा नहीं चाहती। उन्होंने कहा, ष्वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते।

संक्षिप्त खबरें

सीबीआई ने रिश्वत मामले में डीडीए के कार्यकारी अभियंता को गिरफ्तार किया : अधिकारी

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो लाख रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक कार्यकारी अभियंता और एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने उस शिकायत पर कार्रवाई की जिसमें आरोप लगाया गया था कि कार्यकारी अभियंता राहुल मीणा और सहायक अभियंता अंकुश ने लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की और आरोपों का प्रारंभिक सत्यापन किया।

आईएमडी ने केरल के चार जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

केरल,(एजेंसी)। कई हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के चार जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कोल्लम, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के आठ जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि अगले पांच दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, इसके अलावा बृहस्पतिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका है।

पासीघाट सब्जी बाजार में आग से 100 से अधिक अस्थायी दुकान जलकर खाक

अरुणाचल,(एजेंसी)। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट सब्जी बाजार में मंगलवार रात भीषण आग लगने से कम से कम 108 अस्थायी दुकान जलकर नष्ट हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पूर्वी सियांग के आपदा प्रबंधन अधिकारी संगपा ताशी ने बताया कि आग रात करीब नौ बजे लगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब दो करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग में सब्जी और फलों की अस्थायी दुकानों, किराना दुकान, छोटे होटल, कपड़े और स्टेशनरी का सामान बेचने वाली दुकान सहित कई ढांचे पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए।

अनुचित, सदस्यों से व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने का अनुरोध करूंगा : ओम बिरला

नई दिल्ली,(एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों की निंदा की और सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला या पुरुष पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने का अनुरोध किया। कल सदन में जो कुछ भी हुआ वह बेहद अनुचित था और किसी भी सम्मानित सदस्य, खासकर महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला, पुरुष आदि पर व्यक्तिगत टिप्पणियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें...माननीय सदस्य (कल्याण बनर्जी) ने सदन में इसके लिए माफी भी मांगी है और मुझे लिखित में भी दिया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा। प्राधिकरण की टीम पर हमला किया बुधवार को संसद में आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी के कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस के कारण लोकसभा में अराजकता फैल गई। विवाद तब शुरू हुआ जब बनर्जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाए, जिसमें सिंधिया के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी भी शामिल थी, जिसने भाजपा की महिला सांसदों को नाराज कर दिया। उन्होंने तुरंत बनर्जी को सदन से बाहर निकालने की मांग की। कल्याण बनर्जी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वह माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनकी टिप्पणी ष्भारत की महिलाओं पर हमला हैष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विवादास्पद टिप्पणी को सदन से हटा दिया । कल्याण बनर्जी ने बाद में एएनआई को बताया कि उनकी टिप्पणी किसी महिला के खिलाफ नहीं थी और उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, ष्मैंने ऐसा किसी महिला के लिए नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा है। मैंने इसके लिए खेद जताया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के समक्ष टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज कराई। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्ष पर हमला किया और कहा कि भारत ब्लॉक बिना किसी नेतृत्व के काम कर रहा है। शर्मा ने कहा, ष्बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी की विशेषता है. ..कांग्रेस पार्टी के सहयोगी भी कांग्रेस पार्टी की भाषा बोलते हैं। विपक्ष बिना किसी नेतृत्व के काम कर रहा है और इसलिए वे (विपक्षी दल) कांग्रेस के झूठ के जाल में फंस जाते हैं। महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। भारत ब्लॉक दलों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा ।

दिल्ली चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली,(एजेंसी)। दिल्ली कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी और फरवरी 2025 के चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी, यह बात आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कही। केजरीवाल ने रेखांकित किया कि चुनाव के बाद ही लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे जमा किए जाएंगे। प्राधिकरण की टीम पर हमला किया "चुनावों की घोषणा अगले 15 दिनों में होने की संभावना है, इसलिए आपके खातों में पैसे ट्रांसफर करना संभव नहीं है। लेकिन योजना लागू हो गई है। जब हम इस योजना पर काम कर रहे थे, तो कई महिलाएं मेरे पास आईं और कहा कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण 1,000 बहुत कम है। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से (मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए) पंजीकरण शुरू हो जाएगा और पंजीकरण 2,100 प्रति माह होगा, आप प्रमुख ने योजना को लॉन्च करने के लिए आप मुख्यालय में एक कार्यक्रम में कहा।पुलिस को दिया 90 दिन का समय केजरीवाल ने कहा, अगले दो–तीन दिनों में आप कार्यकर्ता घर–घर जाएंगे, आपका नामांकन करेंगे और आपको पंजीकरण कार्ड देंगे। पंजीकरण कार्ड को संभालकर रखें। दिल्ली चुनाव के बाद, 1000 प्रति माह की योजना को ध्2100 प्रति माह की योजना में बदल दिया जाएगा,।

समाज के सभी वर्गों को अधिकार देने की जरूरत : सोरेन

नई दिल्ली,(एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और शोषितों को अधिकार दिए जाने की जरूरत है। सोरेन ने यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक को संबोधित किया। बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में सोरेन ने कहा, "आज रांची में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुआ। संघर्ष से उपजी पार्टी है झारखण्ड मुक्ति मोर्चा। यही कारण है कि हमने हमेशा हक–अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है।" उन्होंने कहा, "विगत विधानसभा चुनाव में आप सभी कर्मठ नेताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत तथा करोड़ों राज्यवासियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप झारखण्ड में मजबूत अबुआ सरकार का गठन हुआ। आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई और जोहार।" उन्होंने कहा, "आने वाले समय में हमें झामुमो परिवार की जड़ों को राज्य के प्रत्येक कोने में पंहुचा मजबूत करने का काम करना हैय वंचित, शोषित समेत समाज के सभी वर्ग को हक–अधिकार देने का काम करना है।" झामुमो नीत गठबंधन 23 नवंबर को झारखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता में आया था। उसने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट हासिल की थीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 24 सीट मिली थीं।

भारतीय उपासना अधिनियम का उल्लंघन कैसे हुआ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला

नई दिल्ली,(एजेंसी)। जैसा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम , 1991 में कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत आज फैसला करेगी कि कैसे भारतीय पूजा अधिनियम का ष्उल्लंघनष् किया जा रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार (आज) को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम , 1991 प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। तिवारी ने एएनआई से कहा, ष्एससी आज फैसला करेगा कि कैसे भारतीय पूजा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि 1947 में अधिनियम में जो तय किया गया था, उसे नहीं बदला जाना चाहिए... मुझे विश्वास है कि एससी इस बात से सहमत होगा कि अयोध्या को छोड़कर इस अधिनियम को कहीं और नहीं बदला जाना चाहिए। झा ने कहा, ष्संसद में एक विधेयक (पूजा स्थल अधिनियम) ऐसे समय में पारित किया गया यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।ष इस बीच, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मांग की कि सभी विवादित स्थानों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि स्थान का वास्तविक चरित्र पता चल सके। ष्यह पूजा स्थल अधिनियम है न कि प्रार्थना स्थल अधिनियम। मंदिर को पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है जबकि मस्जिद प्रार्थना स्थल है। कानून चरित्र की बात करता है, पहचान की नहीं...हम चाहते हैं कि सभी विवादित स्थानों का सर्वेक्षण किया जाए ताकि स्थान का वास्तविक चरित्र पता चल सके. ..यह हिंदू–मुस्लिम का मामला नहीं है... वेदों , भगवद गीता , रामायण में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है , उन्हें पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए और इसके लिए उनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए,ष उपाध्याय ने एएनआई से कहा। यह अधिनियम पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को उनके अस्तित्व को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए अपने श्पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को बहाल करने के हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों को छीन लेता है। कृष्ण प्रियाय भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीय पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीयय सेवानिवृत्त सेना अधिकारी अनिल काबोत्राय अधिवक्ता चंद्रशेखरय वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंहय धार्मिक नेता स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वतीय मथुरा निवासी देवकीनंदन ठाकुर जी और धार्मिक गुरु और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और यह अदालत से संपर्क करने और न्यायिक उपाय मांगने के उनके अधिकार को छीन लेता है। वे यह भी तर्क देते हैं कि अधिनियम उन्हें अपने पूजा स्थलों और तीर्थयात्रा के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है। प्रतिबंधित करने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को मौजूद रखने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम है। जमीयत उलमा–ए–हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

संपादकीय

नशे के खिलाफ अभियान

देश में नासूर बनते नशे के खिलाफ अभियान में यदि 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह प्रेरक पदयात्रा कर सकते हैं तो ऊर्जावान युवा–बुजुर्ग क्यों नहीं। 'नशा मुक्त–रंगला पंजाब' अभियान के अंतर्गत निकाले गए नशा विरोधी मार्च में मंगलवार को मैराथन धावक फौजा सिंह के साथ ही पंजाब के राज्यपाल अस्सी वर्षीय गुलाब चंद कटारिया की आठ किलोमीटर की पैदल यात्रा सुर्खियों में रही। निश्चित रूप से पंजाब सरकार की पहल अनुकरणीय है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव का आंदोलन व्यापक जन भागीदारी से ही सिरे चढ़ सकता है। आज पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में युवा पीढ़ी जिस भयावह तरीके से नशे के दलदल में धंसती जा रही है, वह राष्ट्र के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसका मुकाबला सरकारों के साथ आम आदमी के जुड़ाव से ही संभव है। निश्चित रूप से ऐसी पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक निहितार्थों और प्रतीकात्मक रूप से आयोजित नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभियान को आंदोलन का रूप देकर इस तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही इस तरह के अभियानों से हासिल उपलब्धियों का मूल्यांकन भी जरूरी है। निस्संदेह, औपचारिकताओं के निर्वहन और मीडिया में सुर्खियां बटोरना ऐसे आंदोलन का लक्ष्य तो कदापि नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय का यह कथन सोलह आने सच है कि इस मुद्दे पर बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही महिलाओं की इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निस्संदेह, नशे के नश्तर से महिलाओं को मर्मांतक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अब चाहे पति हो या बेटा, नशे की लत लगने से पूरा परिवार ही संकट में आ जाता है। इसमें दो राय नहीं कि जब पंजाब की नारी शक्ति एकजुट होकर इस मुहिम का नेतृत्व करेगी तो पंजाब अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट सकता है। निश्चित रूप से किसी राज्य या देश की जवानी का नशे के सैलाब में डूबना राष्ट्रीय क्षति ही है। इसके लिये नशे की आपूर्ति रोकने से लेकर प्रयोग तक पर नियंत्रण की राष्ट्रव्यापी मुहिम की जरूरत है। निस्संदेह, नशे के तेजी से बढ़ते शिकंजे से न केवल असामयिक मौतों, लाइलाज बीमारियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि समाज में अपराधों का सिलसिला भी तेज हो जाता है। देखने में आया है कि बड़े अपराधों से लेकर चोरी छीनाझपटी की घटनाओं के मूल में नशाखोरी की भूमिका होती है। कई आपराधिक घटनाओं के मूल में उन कालेज जाने वाले छात्रों की भूमिका पायी गई है, जो नशे के लिये पैसा जुटाने के लिये अपराध की अंधी गलियों में उतर जाते हैं। यह जानते हुए भी यह रास्ता उनके जीवन को बर्बादी की राह पर ले जाता है। निश्चित रूप से समाज विज्ञानियों को भी व्यापक अध्ययन करना चाहिए कि क्यों नई पीढ़ी नशे की ओर तेजी से उन्मुख हो रही है। एक समय था कि पंजाब में आतंक फैलाने के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिये सीमा पार से नशे की बड़ी खेप पंजाब भेजी जाती रही है। चरमपंथियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिये भी इस षड्यंत्र को सुनियोजित तरीके पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों ने अंजाम दिया। हाल के दिनों में बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से लगते भारतीय इलाकों में ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थों को गिराने की साजिशों पर लगाम लगायी है। निश्चित रूप से पहले कदम के रूप में सीमाओं को नशे की तस्करी से निरापद बनाने की जरूरत है। वहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल उन काली भेड़ों को भी बेनकाब करने की जरूरत है जो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही नशे से पीड़ितों को इस दलदल से बाहर निकालने के लिये नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना और पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक उपचार देने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से नशा पंजाब के लिये बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जिसके खिलाफ साझा लड़ाई से ही हम कामयाब हो सकते हैं। सही मायनों में यह स्थिति इस संवेदनशील सीमांत राज्य के लिये ही चुनौती नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय संकट की भी आहट है। केंद्रीय एजेंसियों व पंजाब के शासन–प्रशासन को मिलकर नशे के समूल नाश के लिये व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है।

पूंजीवाद के दंश मगर विरोध सिर्फ पुरुषों का

क्षमा

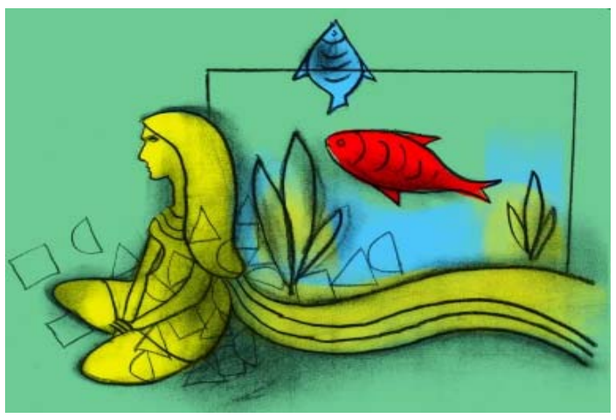

कहा जाता है कि अब तक दुनिया में चार बार फेमिनिज्म या स्त्रीवाद की लहर चली है। पहली बार स्त्रीवाद की बात उन्नीसवीं सदी के मध्य से लेकर बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों तक सुनी गई। फिर दूसरी बार स्त्री अधिकारों की तेज आवाजें 1960 से लेकर 1980 के शुरुआती वर्ष में देखी गईं। आपको याद होगा कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी घोषित किया था। भारत में भी यह एक तरीके से स्त्रीवादी आंदोलन की शुरुआत थी। अपने यहां स्त्री अधिकारों की बातों को मीडिया ने भी उठाया। अमेरिका की तरह मीडिया बैशिंग औरतों को नहीं झेलना पड़ी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तरह–तरह के कानून बनाए गए। यहां तक कि भारत में तो इंदिरा गांधी 1966 में ही प्रधानमंत्री बन गई थीं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने का इंतजार अभी तक महिलाओं को है। वहां तो वोट के अधिकार तक के लिए महिलाओं को सत्तर साल तक संघर्ष करना पड़ा था। जबकि हमारे यहां महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। स्त्री अधिकारों की बात अपने यहां भी उन्नीसवीं सदी में पुनर्जागरण के नायकों और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताओं ने जोर–शोर से उठाई थी। यों हजारों वर्षों से स्त्री की आफतों की बात होती रही है। थेरिगाथाओं में बौद्ध भिक्षुणियों की ये आवाज और शिकायतें सुनी जा सकती हैं। तुलसीदास की वे पंक्तियां भी उद्धृत करने योग्य हैं– केहि विधि नारि रची जग माहीं, पराधीन सपनेहु सुख नाहीं। बंगाल के महान उपन्यासकार शरतचंद्र ने भी अपने साहित्य में इस तरह के मुद्दों को खूब उठाया। हिंदी में भी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि के साहित्य में स्त्रियों की समस्याओं की बात प्रमुखता से मिलती है। स्त्रीवाद की तीसरी धारा 1990 से 2010 तक मानी गई और 2010 के बाद चौथी धारा की बात की जा रही है। इसमें पितृसत्ता से पूरी मुक्ति और औरतों को समान वेतन देने की बात प्रमुखता से उठाई गई है। फिर 2018 में ट्विटर के जरिए दक्षिण कोरिया में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे 4बी का नाम दिया गया। इसमें स्त्रियां एक कदम और आगे जा पहुंचीं। कोरियाई भाषा में ब से शुरू होने वाले चार शब्दों का प्रयोग किया गया। ये शब्द हैं– बिहोन– पुरुष से शादी नहीं, बिकुलसन दृ कोई बच्चा नहीं, बियोनाए– पुरुषों के साथ डेटिंग भी नहीं, बिसेकसेउ, पुरुषों के साथ यौन सम्बंध नहीं। इसे फोर नोज भी कहते हैं। यानी कि महिलाओं के न कहने का अधिकार। इस आंदोलन में कहा गया था कि जो स्त्रियां अकेली रहती हैं, विवाह नहीं करतीं, जिनके बच्चे नहीं होते, कोरियाई सरकार और समाज उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखता। महिलाओं को नौकरियों में भी पुरुषों के मुकाबले कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। औरतों को सिर्फ उपभोक्ता समझा जाता है। पूंजीवादी समाज उन्हें हर तरह के अधिकार से वंचित करता है। समाज महिलाओं को सिर्फ मां बनाना चाहता है। जबकि मां बनना, न बनना, औरत का अपना अधिकार है क्योंकि यह उसका शरीर है। इसलिए वे अब पुरुषों से किसी भी प्रकार का सम्बंध नहीं रखना चाहतीं। वे ब्यूटी पार्लर्स का भी बहिष्कार कर रही हैं। कमाल ये है कि महिलाओं ने अपनी आफतों के लिए पूंजीवाद को दोषी ठहराया है, मगर बहिष्कार वे पुरुषों का कर रही हैं। जबकि पूंजीवाद में पुरुष भी मात्र उपभोक्ता में तब्दील कर दिए गए हैं, और वे भी शिकार ही हैं। अमेरिका में जब से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस को हराकर चुनाव जीता है, तब से वहां भी 4बी आंदोलन की आवाज सुनाई दे रही है। स्त्रियां पुरुषों का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि ट्रंप को गर्भपात विरोधी माना जाता है। यहां भी औरतों का मानना है कि वे मां बनें या न बनें , यह उन्हें ही तय करने दीजिए। कोई पुरुष उन्हें इसके ऊपर लाद नहीं सकता। ट्रंप अपने भाषणों में बार–बार कहते रहे हैं कि अमेरिकी समाज की बड़ी जरूरत परिवार और परिवार के मूल्यों की वापसी है। पूर्व उपराष्ट्रपति अल गेर की पत्नी तो परिवार की वापसी का आंदोलन 1993 से चला रही हैं। लेकिन अमेरिकी स्त्रियां कोरियाई स्त्रियों की तरह ही कह रही हैं कि उन्हें भी अपने जीवन में कोई पुरुष नहीं चाहिए। हम उन्हें सत्ता में आने से रोक नहीं सकते, मगर उनसे दूर तो हो सकते हैं। उनका मानना है कि वे जैसे चाहें जीवन जीएं, यह उनका अधिकार है। इसीलिए औरतें कह रही हैं कि न वे सजेंगी, संवरेंगी, न पेडिक्योर कराएंगी, न मेनिक्योर। वे डेटिंग एप्स और वेबसाइट्स को अलविदा कह रही हैं। पुरुषों के सम्पूर्ण बहिष्कार की बातों से कोई भी समाज कहां जा सकता है। एक तरफ स्त्रियां पुरुषों का पूरी तरह से बहिष्कार चाहती हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं, जो स्त्रियों को मामूली मानव अधिकार तक नहीं देते। वे सदियों पुराने धार्मिक कानूनों से उन्हें हांकते हैं और इसे जस्टीफाई भी करते हैं। तालिबानों ने तो महिलाओं की शिक्षा, उनके बाहर निकलने, संगीत सुनने आदि तक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 4बी चलाने वाली स्त्रियों की नजर इन महिलाओं पर नहीं जाती। क्या ये औरतें नहीं। इनके कोई मानव अधिकार नहीं। ये स्त्रियां, स्त्री विमर्श से बाहर क्यों हैं। अपने यहां भी जब सरकार ने तीन तलाक के खात्मे का निर्णय किया था, तो बहुत–से लोगों ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देकर इसका विरोध किया था। यदि तलाकशुदा मुसलमान स्त्रियों की

हालत जाननी हो, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सईदा हमीद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दृवायस आफ द वायसलैस पढ़ी जा सकती है, जिसमें इन अभागी औरतों का ऐसा वर्णन है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर धर्म के ठेकेदारों को अपनी ही स्त्रियों की चिंता क्यों नहीं होती। देखने की बात यह है कि अमेरिका में एक ट्रेडिशनल वाइफ मूवमेंट भी है, जिसमें बहुत सी स्त्रियां कहती हैं कि वे अपने घरों में रहना चाहती हैं। पति और बच्चों की देखभाल करना चाहती हैं। पति के लिए भोजन पकाना तथा हर तरह के अन्य कामों में उनकी दिलचस्पी है। वे घर और दफ्तर के बीच दौड़ती रहना नहीं चाहतीं। अगर ध्यान से देखें तो जब भी कोई विमर्श जन्म लेता है, उसका प्रति विमर्श भी साथ–साथ आंखें खोलता है और उसे चुनौतियां देने लगता है। क्या दुनिया के सारे पुरुष स्त्रियों को सता रहे हैं या बहुसंख्यक वे भी पीड़ित और सताए गए हैं। चांदी की चम्मच जिनके मुंह में हैं, वे स्त्री हों या पुरुष, पूरी दुनिया में मजे में हैं और उनकी सम्पत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। निजी जीवन में पुरुष नहीं चाहिए, तो जिस आत्मनिर्भरता के परचम को लहरा रही हैं, कार्यस्थलों से भी क्या पुरुषों को खदेड़ देंगी। यदि इस समाज में सिर्फ औरतें रहेंगी, तो क्या वास्तव में तमाम तरह के शोषण और अन्याय से मुक्ति मिल सकेगी। स्त्रियों का राज होगा, तो क्या सत्ता चलाने का तंत्र बदल जाएगा। शायद नहीं, क्योंकि सत्ता चलाने के अपने तंत्र होते हैं और दुनिया में कोई भी सत्ता हो, वह निरंकुशता से ही चलती है। कोई सत्ता भी इससे मुक्त नहीं होगी। इतिहास भी इस बात का गवाह है।

कनाडा को अमेरिका का राज्य बना देंगे

आदित्य

अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक बयानों और फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो आए दिन ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं कि जिसे लगता है कि उनके शपथ लेने के बाद वाशिंगटन की नीतियों के साथ ही विदेश नीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। अमेरिका में फिलहाल 50 राज्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव ने कनाडा की जमीन हिला दी है। पूरा भारत भी ये खबर सुनकर हैरान है। दुनियाभर के लोग पहले तो इस खबर को झूठ मान रहे थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस खबर पर मुहर लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ एप पर एक तस्वीर डालकर खबर की पुष्टि की है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका में खड़े होकर कनाडा को देख रहे हैं। ताकी कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाया जा सके। इस तस्वीर में ये भी दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के झंडे को अपने कब्जे में ले लिया है। तस्वीर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है ओह कनाडा! हैरानी की बात देखिए कि कनाडा का राष्ट्रगान भी ओह कनाडा से ही शुरू होता है। आज आपको बताते हैं कि ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को डांटते हुए ऐसा क्यों कहा है कि वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कनाडा और अमेरिका के बीच कितना व्यापार होता है? ट्रंप की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी कनाडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? इसके साथ ही आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस तरह के तेवर का क्या भारत पर भी कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन कनाडा से अमेरिका आने वाले समानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे। अगर टैरिफ 25 प्रतिशत बढ़ता है तो अमेरिका में मिलने वाला कनाडा का सामान महंगा हो जाएगा। अमेरिका का कोई भी आदमी कनाडा का सामान नहीं खरीदेगा और इसका सीधा असर ओटावा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका के इस ऐलान से घबराकर जस्टिन ट्रूडो रातों रात ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गए। जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ न बढ़ाने के लिए भीख मांगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया। ट्रंप ने भड़कते हुए ट्रूडो से कहा कि यदि आपको हमारे फैसले से दिक्कत हो रही है तो आप कनाडा के बॉर्डर को खत्न करिए और खुद अमेरिका का हिस्सा बन जाइए। ट्रंप के टैरिफ लगाने की बात पर ट्रूडो ने कहा कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। फॉक्स न्यूज के अनुसार, ट्रंप ने जवाब दिया, तो आपका देश तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि वह अमेरिका को 100 बिलियन डॉलर का चूना न लगा दे? ट्रंप ने जस्ध्टध्नि ट्रूडो को दो टूक कहा कि अमेरध्कि के साथ 100 बिलध्यिन का व्ध्यापार घाटा है। इसे खत्ध्म करना ही होगा, वरना हम कड़े फैसले लेने के लध्एि मजबूर होंगे। कनाडा चाहे तो अमेरध्कि का 51वां राज्ध्य बन सकता है। हम जस्ध्टध्नि ट्रूडो को उसका गवर्नर बना देंगे। इस पर ट्रूडो ने कहा कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री का पद बेहतर है। लेकिन ट्रंप की इस टिप्ध्पणी पर जस्ध्टध्नि ट्रूडो को सांप सूंघ गया। कनाडा, 1867 से एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान अमेरिका से अलग है। दोनों देशों के राजनीतिक ढांचे अलग–अलग हैं। कनाडाई संविधान और ब्रिटिश राजशाही के प्रति निष्ठा कनाडा को एक विशिष्ट पहचान देती है। कनाडाई जनता और राजनेताओं ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। जनता के लिए यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है, क्योंकि यह उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पड़ोसियों के बीच व्यापार घाटा निस्संदेह बढ़ा है। कनाडा के साथ, संबंध ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत संतुलित रहे हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों में बदलाव देखा गया है। मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा आयात की बढ़ती लागत और मात्रा के कारण। दूसरी ओर, मेक्सिको ने हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार अधिशेष में विस्तार देखा है, जो ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रतिस्पर्धी उद्योगों के बढ़ते आयात से प्रेरित है। ट्रम्प व्यापार घाटे को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी के रूप में देखते हैं जिसे एड्रैस करने की आवश्यकता है। व्यापार प्रतिबंध लगाकर उनका लक्ष्य घरेलू अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। लेकिन अमेरिकी निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने और आयात शुल्क लगाने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मुद्रास्फीति में अपेक्षित वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के अलावा, टैरिफ 2020 से संयुक्त राज्य अमेरिका– मेक्सिको –कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) द्वारा बढ़ावा दिए गए आर्थिक एकीकरण को भी बाधित कर सकते हैं। कनाडा दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार पर आश्रित देश है। कनाडा का 75 फिसदी निर्यात अमेरिका को होता है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान उन्होंने मेक्सिको,अमेरिका और कनाडा नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट (नाफ्टा) के तहत पहले से होते आए व्यापार पर फिस से बातचीत करने के लिए कदम उठाए थे। उस वक्त वो ऑटो सेक्टर पर 25 फीसदी टैरिफ को लेकर भी विचार कर रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में हर दिन दोनों देशों के बीच लगभग 3.6 बिलियन कनाडाई डॉलर (2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य की चीजों और सेवाओं का व्यापार हुआ था। ट्रंप की ओर से कभी टैरिफ लगाने की धमकी तो कभी ट्रूडो को गवर्नर तक बता देने के बावजूद कनाडा की तरफ से कुछ खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बल्कि पूरे मामले पर ट्रूडो सरकार ने चुप्पी साध रखी है। कनाडा पहले से ही आर्थिक बदहाली झेल रहा है। वैसे ही ट्रंप के मूड का कुछ पता नहीं और अगर टैरिफ बढ़ जाती है तो पैसे की किल्लत और ज्यादा बड़ जाएगी। कनाडा 75 प्रतिशत निर्यात तो अमेरिका को ही करता है। 25 प्रतिशत की टैरिफ लगने से उसका लगभग खाली हो चुका खजाना और बिल्कुल ही साफ हो जाएगी। कनाडा में चुनाव भी होने हैं। इसके लिए भी पैसा चाहिए। वैसे भी ट्रूडो के इस चुनाव में जीतने की संभावना न के बराबर है। इसलिए भी सारे अपमान का घूंट पीकर ट्रूडो ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आपसी रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। एक सोशल पोस्ट में ट्रंप ने ट्रूडो को निशाना बनाते हुए कनाडा का गवर्नर बताया। अब ट्रूध्डो की तरफ से कमला हैरिस का नाम लेकर इशारों इशारों में ट्रंप पर निशाना साधा है। वॉयस फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार को महिलाओं की प्रगति पर हमला बताया।

और भी गम हैं पर्ची–खर्ची के सिवाय

शमीम

हरियाणा में इस साल जो शब्द सबसे ज्यादा बोला गया, वो है– पर्ची–खर्ची। बिना पर्ची–खर्ची के नौकरियों का मिलना हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि पर्ची–खर्ची ने तीसरी बार सरकार बनवा दी। पर सच्चाई यह है कि खर्ची तो चाहे हरियाणा में बंद हो जाये पर पर्ची का वर्चस्व हमेशा की तरह कायम रहेगा। डॉक्टर की पर्ची में रोगियों के नवजीवन की दवाइयों की सूची होती है तो परीक्षा भवन में बैठे विद्यार्थी की जेब में भरी पर्चियां उसकी नैया पार लगाती हैं। पर्ची चाहे डॉक्टर की हो चाहे परीक्षार्थी की, उनमें एक समानता है कि दोनों ही दिल बिठाने का काम करती हैं। डॉक्टर की पर्ची दवाइयों का बिल बनाती है तो रोगी का दिल बैठता है और परीक्षार्थी को जब यह पता चलता है कि उसकी पर्ची में लिखा सवाल परीक्षा में आया ही नहीं तो विद्यार्थी का दिल बैठने लगता है। 'उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं' सवाल के जवाब में नकलची ने लिखा था कि वह प्रदेश जहां उत्तर का परीक्षा में बैठने से पहले ही पता चल जाये, उत्तर प्रदेश कहलाता है। जब अध्यापक ने दो बच्चों से पूछा कि तुम्हारे उत्तर एक जैसे कैसे हैं तो बच्चों का जवाब था कि प्रश्न भी तो एक जैसे ही थे। जब कभी विद्यार्थी स्कूल न आने की वजह बताता है कि वह बीमार हो गया था तो अध्यापक का फरमान होता है कि कल डाक्टर की पर्ची लेकर आना। उस्ताद बच्चे का जवाब होता है कि उसने तो झाड़ा लगवाया है और एक पर्ची में भभूत मिली है, कहो तो लाऊं? एक नकलची देव के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला– हे प्रभु! इस बार पास करवा दो और सरकारी नौकरी लगवा दो। उसके बिना चढ़ावे के हाथ देखकर उन्होंने पूछा– क्या बात, चढ़ावे के लिये कोई नारियल, सेब, केला नहीं लाये? प्रार्थी बोला– आप कर्म करो, फल की चिंता न करो। स्कूल–कॉलेज में उसे ही सच्चा मित्र माना जाता है जो समय पर सही प्रश्न की पर्ची पहुंचा दे। यह और बात है कि लड़के तो पर्ची से नकल करने पर उसे एक के बाद दूसरे को देते रहते हैं पर लड़कियां नकल करने के बाद पर्ची को ऐसे पचा जाती हैं जैसे भ्रष्ट करोड़ों डकार जाते हैं और पता भी नहीं चलता। एक बर की बात है अक इम्तहान मैं नत्थू कती गुमसुम बैठ्या था। मास्टरणी बोल्ली– रोल नंबर भूल आये बेटा? नत्थू चुप बैठ्ठा रह्या। मास्टरणी नैं हटकै बूज्झी– बेटा पैन भूल आये क्या? नत्थू परेशान होकै एकदम चीखता सा बोल्या– चुप हो ज्या बुआ। तेरै पैन अर रोल नंबर की आग लाग री है। उरै मैं पर्ची दूसरे सब्जैक्ट की पाड़ ल्याया।

न्यायिक सुधारों के दीर्घकालीन प्रभावों के यक्ष प्रश्न

डॉ. सुधीर

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद से देश भर में इन नए कानूनों को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये नये कानून भारतीय कानूनी प्रणाली के आधुनिकीकरण और सरलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को बदलकर, ये नए कानून देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और न्याय व्यवस्था में तेजी लाने, लंबित मामलों को जल्दी निपटाने में मदद करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपराधों की जांच और मुकदमों को तय समय सीमा में निपटाने की व्यवस्था है, जिससे न्याय में देरी नहीं होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान किए गए हैं, जिससे सुरक्षा की भावना बढ़ी है और अपराधों पर नियंत्रण की उम्मीद है। इन कानूनों के माध्यम से सरकार कानून का शासन स्थापित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहरा रही है। कई लोग मानते हैं कि ये कानून देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। इन कानूनों में तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को स्वीकार करना, जो जांच प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इन नए कानूनों में कई जगह अस्पष्टताएं हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी चिंतित हैं कि इन कानूनों का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए किया जा सकता है। कुछ विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों को बनाने में पर्याप्त चर्चा और विचार–विमर्श नहीं किया गया है। कुछ का मानना है कि इन कानूनों के तहत सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दे दी गई हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। कई विपक्षी दल और नागरिक समाज संगठन इन कानूनों को लोकतंत्र के लिए चुनौती मानते हैं, यह चिंता जताते हुए कि ये कानून सरकार को विरोधियों को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण का एक उपकरण प्रदान कर सकते हैं। कानूनों में अस्पष्ट और व्यापक शब्दों के प्रयोग से इनके दुरुपयोग का डर है, जैसे कि 'देशद्रोह' के दायरे को लेकर उठे सवाल। विपक्ष का आरोप है कि इन कानूनों को संसद में बिना पर्याप्त चर्चा और बहस के जल्दबाजी में पारित किया गया। उनका कहना है कि ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, विशेषकर गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित प्रावधानों को लेकर चिंता जताई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून पुलिस को अधिक शक्तियां देंगे, जिससे नागरिकों का दमन बढ़ सकता है। विद्वानों के अनुसार, ये कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए चुनौती हो सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय और विपक्षी दलों का आरोप है कि ये कानून विशेष रूप से उनके लिए चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। लोग चिंतित हैं कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और अधिकारों का हनन हो सकता है। कुछ लोग नए कानूनों का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ को संदेह है। कई का मानना है कि इन कानूनों के प्रभाव का सही आकलन करने में समय लगेगा। तर्क देते हैं कि ये कानून देश में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, अपराधों पर अंकुश लगाएंगे और न्यायपालिका को अधिक प्रभावी बनाएंगे। वकीलों का एक वर्ग इन कानूनों का विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेंगे। नागरिक समाज के कई संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ हैं। नए कानून में राजद्रोह के दायरे को लेकर कई सवाल उठे हैं। विपक्ष का तर्क है कि यह प्रावधान सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जमानत मिलने के मानदंडों को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। पुलिसिया हिरासत के दौरान लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। नए कानून में डिजिटल निगरानी के प्रावधानों को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कुछ का मानना है कि ये नए कानून काफी जटिल हैं और आम लोगों को इन्हें समझने में मुश्किल होगी। अदालतें इन कानूनों की व्याख्या कैसे करती हैं, और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन कानूनों को किस तरह से लागू करती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हुए बदलावों को लेकर जनता की प्रतिक्रियाएं विविध हैं। इन कानूनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। इन कानूनों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता है। देखना बाकी है कि ये कानून जमीनी स्तर पर कैसे लागू किए जाते हैं और उनका आम नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून एक जीवंत दस्तावेज है और समय के साथ इसमें बदलाव होते रहते हैं।

आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले की जांच तेज ,जौनपुर पहुंची पुलिस आरोपितों के घर नोटिस किया चस्पा

मामले की जांच पड़ताल करने पुलिस टीम पहुंची दीवानी न्यायालय, अधिवक्ताओं से कर रही बातचीत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बेंगलुरु की मराठाहल्ली पुलिस ने आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले की जांच तेज कर दी है। एक टीम जौनपुर में भी आयी ताकि मृतक अतुल सुभाष के ससुराल वालों और अन्य संबंधियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा सके। दरअसल, अतुल ने सुसाइड नोट में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया को जिम्मेदार बताया था। इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिलहाल, निकिता कहां है? ये किसी को नहीं पता लेकिन उसके घरवाले जौनपुर में ही है और मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस के पहुंचने से सभी घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। रात के अंधेरे में उनके भागने का वीडियो भी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर बीते सोमवार को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले अतुल लंबा–चौड़ा सुसाइड नोट और रिकॉर्डेड वीडियो छोड़ गए है, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उनका वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है। वहीं, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज जांच–पड़ताल शुरू कर दी है। मराठाहल्ली पुलिस ने अतुल सुभाष के घर से एक डेथ नोट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए है। अदालत की मंजूरी के साथ, महत्वपूर्ण सबूतों के लिए इन वस्तुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। अतुल ने पहले ही सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पासवर्ड लिख लिए थे, जिससे जांच आसान हो गई है। उधर, मामले में अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 3(5) का केस अतुल की पत्नी और अन्य तीन के खिलाफ दर्ज किया है। वही इस मामले में गुरुवार रात बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची और अपनी जांचपड़तला तेज कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपितों के घर नोटिस चस्पा कर दिया है।इसके बाद दीवानी न्यायालय पहुंच कर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से मुलाकात कर मामले की जानकारी ले रहे हैं।साथ ही इस मामले से जुड़ी जज से भी बातचीत कर सकते हैं।इससे पहले निकिता की मां ने बात करते हुए अपनी बेटी निकिता और परिवार पर लगाए गए उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगे है, सारे निराधार है। मै सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला है। मेरी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए नहीं बोल सकती। इन सबके बीच निकिता सिंघानिया की मां निशा और उनका साला रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाकर जाती हुई दिखाई दीं। इस दौरान मीडिया के सवालों से बचती हुई अतुल की सास निशा का वीडियो भी सामने आया है। वह रिपोर्टर के हाथ जोड़ रही है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है और फिर वो बाइक पर बैठकर चली गईं।

स्वयम पोर्टल के कोर्सेज डिग्री के लिए मान्य,अश्नलाइन कोर्सेस के लिए स्वयम पोर्टल है उपयोगी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा स्वयम पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को किया गया। विश्वविद्यालय के स्वयं पोर्टल के नोडल अधिकारी प्रोफेसर प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि स्वयम पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन कोर्सेस के लिए विकसित की गई वेबसाइट है जिसके माध्यम से स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर दस नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, इग्नू, यूजीसी के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराते हैं। उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वयम पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्सेज को उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए स्वीकार कर लिया गया है। स्वयम के सह–नोडल अधिकारी डॉ. नितेश जायसवाल ने पाठ्यक्रम के क्रेडिट और उनके चुनाव के संबंध में विस्तार से बताया। डॉ जायसवाल ने बताया कि विद्यार्थी स्वयम पोर्टल पर लॉगिन कर विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन कोर्सेस का चयन कर

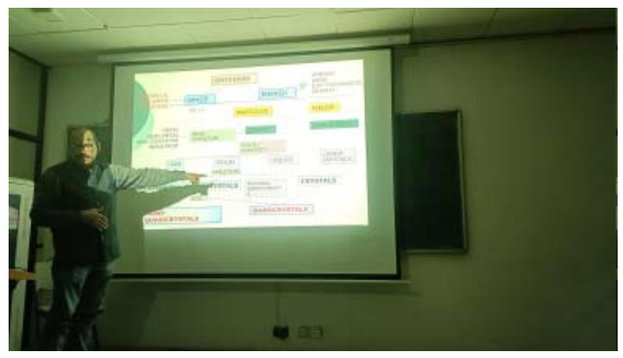

उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। ये कोर्सेज उनके डिग्री के लिए मान्य होंगे। ये कोर्सेज मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल या स्किल के हो सकते हैं। स्वयम के सह–नोडल अधिकारी डॉ. नीरज अवस्थी ने ने बताया कि विद्यार्थी स्वयम पोर्टल द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 20: क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा चयनित कोर्सेज की परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से देने एवं उत्तीर्ण करने के पश्चात अर्जित अंक व क्रेडिट उसके मार्कशीट पर अंकित किए जाएंगे।

निर्मलीकुंड व आसपास तेंदुएं की आहट पर डीएफओ ने लोगो को किया जागरुक

अयोध्या। निर्मलीकुंड व माझा सहित अन्य क्षेत्रों मे तेंदुएं के विचरण करने की आहट पर वन विभाग काफी सतर्कता बरत रहा है।जिसको लेकर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तेंदुएं को पकड़ने के लिए वहां पर सीसीटीवी कैमरा,पिजडे आदि लगाकर पैनी नजर बनाये रखे है।वही वहां के लोगो को तेंदुएं से बचाने के लिए शुक्रवार को निर्मलीकुण्ड के निकट मांझा क्षेत्र में चौपाल कार्यकम के तहत मानव वन्य जीव संघर्ष पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया।जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा भाग लिया।इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी प्रणव जैन ने लोगो को जागरूक करते हुए कहा कि आप सभी घर के आस–पास पर्याप्त रोशनी रखें तथा झाड़ियों की समय–समय पर साफ–सफाई करते रहें। छोटे बच्चों को अकेले न घूमने दें।रात्रि में छावनी क्षेत्र में आवागमन न करें।उन्होंने कहा कि तेंदुए को देखने पर उसके पास जाने या उसे छूने या घूरने का प्रयास न करें। यदि छावनी क्षेत्र में जाएं तो समूह में जाएं और अपने साथ टार्च व डण्डा अवश्य रखें तथा तेज आवाज में बात्त करें व दिखाई देने पर सामूहिक रूप से शोर करें।तेंदुआ देखने पर उसे पकड़ने, भगाने अथवा मारने का प्रयास कदापि न करें। वन विभाग को तुरन्त सूचित करें।इस मौके पर प्रणव जैन के अलावा के०एन०सुधीर,उप प्रभागीय वनाधिकारी,, तथा प्रभाग के सभी क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं सम्बन्धित स्टॉफ उपस्थित रहें।

आने वाले समय में उर्जा का नया श्रोत बनेगा हाइड्रोजन: डा. टी. पी. यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रज्जू भैया संस्थान के नैनो साइंस केंद्र में हाइड्रोजन गैस उर्जा के संचय विषय पर व्याख्यान शुक्रवार को आयोजित किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डा. ठाकुर प्रसाद यादव ने कहा कि हाइड्रोजन स्वक्च उर्जा का नया श्रोत हो सकता है हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण में उपलब्ध है और इससे उत्पन्न उर्जा कार्बन उतसर्जन रहित होता है इस वजह से हाइड्रोजन उर्जा के प्रयोग को लेकर तमाम शोध हो रहे है ।इस हाइड्रोजन उर्जा के ईधन के रूप में प्रयोग को लेकर देश–विदेश में बहुत से शोध चल रहे है द्य इस क्रम में इलहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्राध्यापक डा. ठाकुर प्रसाद यादव ने अपने व्याख्यान में यह बताया कि हाइड्रोजन गैस उर्जा का एक स्वाच माध्यम है और यह ध्रती पैर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन इसको संचित करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है द्य इस उर्जा का प्रचुर मात्र में सदुपयोग नहीं हो पा रहा है इसके कई व्यवहारिक कारण है जैसे हाइड्रोजन उर्जा का संचय एवं संचित हाइड्रोजन गैस का अवाश्कतानुसार उपलब्ध न हो पाना हैद्य भौतिक विज्ञान विभाग के युवा वैज्ञानिक डॉ. ठाकुर प्रसाद यादव ने भारत के हाइड्रोजन मैन के नाम से विख्यात पदमश्री प्रो. ओएन श्रीवास्तव के निर्देशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना शोध कार्य किया है और वह स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी टॉप दो प्रतिशत वैज्ञानिको की सूची में शामिल है। डॉ. यादव भौतिकी के नैनो पदार्थ, हाइड्रोजन संभरण और ऊर्जा भंडारण पर किए गए शोध कार्य के कारण सुर्खियों में रहे हैं। उनके १५० से अधिक शोध पत्र और 20 पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.वंदना सिंह की प्रेरणा से विद्यार्थियों में शोध के प्रति आकर्षण विकसित करने के लिए ऐसे आयोजन किये जा रहे है। रज्जू भैया संस्थान के निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार यादव ने स्वागत तथा नैनो विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डा सुजीत कुमार चौरसिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

प्राणघातक प्रतिबंधित चाइनीज मांझा और पॉलीथिन ना बेचें व्यापारी और नाही सड़क पर करें अतिक्रमण : इंदु सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। प्राण घातक 'चाइनीस मांझा' एवं प्रतिबंधित 'काली पालीथीन' ना बेचें व्यापारी सड़क पर नाली के बाद सड़क पर 'अतिक्रमण' ना करें व्यापारी। उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष एवं प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदु ने नगर जौनपुर सहित जनपद के सभी व्यापारियों से कही है। उन्होंने कहा कि आए दिन चाइनीज मांझे से आमजन जख्मी हो रहे यहां तक कि लोगों की जान भी जा रही है। चाइनीज मंझा प्रतिबंधित है इसे न बेचें और ना ही खरीदें इसका शिकार हम आप भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे अच्छे स्वास्थ और पर्यावरण के लिए पॉलीथिन भी प्रतिबंधित है विशेष रूप से काली पॉलीथिन सभी व्यापारी और आमजनता से अपील है कि प्रतिबंधित पालीथीन ना बेचें और ना ही उपयोग करें। पॉलीथिन में गर्म खाना, चाय और खाने पीने की गर्म चीजें अक्सर आम जनता उपयोग करते हुए दिखाई देती है यह भी प्राणघातक है और हमारे स्वास्थ और पर्यावरण के लिए हानिकारक और जानलेवा है। शहर में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाली क्रॉस कर के सड़कों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना करें जिससे कि यातायात व्यवस्था बाधित हो और जाम की स्थिति पैदा हो। इन सभी मुद्दों पर जिला प्रशासन से वार्ता हुई है, ऐसे में पहले से ही समस्त बिंदुओं पर व्यापारी गण अपने को नियमित कर लें कल को जिला प्रशासन किसी को इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पकड़ेगा तो हमें आपको विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए सम्मानित व्यापारी गण उपरोक्त सभी बिंदुओं पर अपने आप को नियमित कर लें। उक्त जानकारी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला महामंत्री आरिफ हबीब ने दी है।

ब्रह्म बाबा मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष ने एसडीएम सदर को सौपा ज्ञापन

अयोध्या। अयोध्या – प्रयागराज राजमार्ग पर कोतवाली नगर के पूरे हुसैन खां स्थित ब्रह्म बाबा स्थल को लेकर दो समितियो के बीच विवाद गहरा गया है।जिसको लेकर ब्रम्हा बाबा मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष रामदास व पुजारी अनिल दास व कई लोगों ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौपा।ज्ञापन के माध्यम सें उन्होंने पौराणिक स्थल ब्रम्ह बाबा के पुजारी अनिल दास को नियुक्त करने व अवैध ट्रस्ट को हटाने की मांग किया।इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष यादव पर गंभीर आरोप लगाया गया।आरोप मे कहा गया कि संतोष यादव ट्रस्ट बनाकर कब्जा कर रहे।संतोष यादव पर पुजारी अनिल यादव को निकालने का आरोप लगाया। संतोष यादव के मुताबिक पुजारी अनिल यादव सिद्धार्थनगर का हिस्ट्रीसीटर हैं जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है।पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आधारकार्ड मांगा गया था।पिछले कई महीने से आधार कार्ड नही दे रहा है।जिसके कारण पुजारी का सत्यापन नहीं हो रहा है।आरोप के मुताबिक समिति के अध्यक्ष रामदास ब्रह्मा बाबा स्थल की जमीन पर होटल बनाकर कर कब्जा कर रहा था।कार्य रोकने के बाद समिति बनी है।संतोष यादव के ट्रस्ट पर ब्रम्ह बाबा मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष रामदास ने कोर्ट में मुकदमा किया है।

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ में विंटर स्कूल 2024

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ में 9–13 दिसंबर, 2024 तक आयोजित ष्एक्सपेंडिंग रिसर्च होराइजन्सष पर पांच दिवसीय विंटर स्कूल का शुक्रवार को समापन हुआ। इस वर्ष विंटर स्कूल में अकादमिक लेखन और

प्रकाशित होना, निगमनात्मक (डिडक्टिव), आगमनात्मक (इंडक्टिव) और अपवर्तनीय तर्क द्वारा सिद्धांत तैयार करना, हार्वर्ड केस लिखना, डिजिटल युग में गुणात्मक शोध (क्वालिटेटिव रिसर्च) और शोध में एआई का उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। विंटर स्कूल का उद्घाटन 9 दिसंबर को हुआ, जहाँ जयपुरिया, लखनऊ के डीन रिसर्च डॉ. अनुभव मिश्रा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. नृपेंद्र राणा, प्रोफेसर, क्वीन्स बिजनेस स्कूल, बेलफास्ट, यूके थे। विंटर स्कूल ने सभी शोध विद्वानों और शिक्षाविदों के लिए शिक्षण और शोध विधियों का एक अनूठा और मौलिक अवलोकन प्रस्तुत किया। पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरेट विद्वानों के साथ–साथ शिक्षाविदों को शिक्षण शिक्षाशास्त्र और शोध विधियों की बेहतर समझ रखने और अपने शोध में मदद करने के लिए नए सॉफ्टवेयर और मॉडल के बारे में जानने के लिए एक मंच प्रदान करना था। यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम बेहतर शोध लेख तैयार करने और उन्हें शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित करने पर केंद्रित था, जिससे प्रतिभागियों को शोध पत्र प्रकाशन और थीसिस लेखन के लिए फायदेमंद शोध कौशल विकसित करने में मदद मिली। विंटर स्कूल 2024 के प्रमुख आकर्षण में विंटर स्कूल, डॉक्टरेट संगोष्ठी (कोलोकियम), छात्र प्रतियोगिता, पेपर डेवलपमेंट वर्कशॉप, 3–मिनट थीसिस पिच आदि सहित कई कार्यक्रम शामिल थे। इस सहयोगी मंच ने नेटवर्किंग को प्रोत्साहित किया, प्रतिभागियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया और शिक्षा और अनुसंधान के भविष्य को आकार दिया। डॉ. नृपेंद्र राणा, प्रोफेसर, क्वींस बिजनेस स्कूल, बेलफास्ट, यूकेय सुश्री चौताली शर्मा, के–12 और अन्य बिक्री–दक्षिण एशिया, टर्निटिन एपीएसीय डॉ. आलोक दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएम लखनऊय डॉ. सुजीत शर्मा, प्रोफेसर, आईआईएम नागपुरय डॉ. शैलेश पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर, डॉ. सुभादीप रॉय, प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबादय डॉ. वर्षा जैन, चेयर प्रोफेसर– एमआईसीए, अहमदाबादय सुश्री संगीता मेनन, एमराल्ड पब्लिशिंग में प्रकाशन संबंध प्रबंधकय डॉ. शिव कक्कड़, उपाध्यक्ष, एआई इनिशिएटिव्स, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंटय डॉ. सुधीर राणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूएईय विंटर स्कूल 2024 के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे। विंटर स्कूल में अकादमिक लेखन और प्रकाशित होना, डेस्क अस्वीकृति से बचना और शोध में नैतिकता को बनाए रखना, आर का उपयोग करके वित्त के लिए अर्थमिति, डिडक्टिव, इंडक्टिव और एबडक्टिव रीजनिंग द्वारा सिद्धांत उत्पन्न करना, हार्वर्ड केस लिखनारू एक विशेषज्ञ से अंतर्दृष्टि, प्रकाशनों के जीवन–चक्र का प्रबंधन, डिजिटल युग में गुणात्मक शोध, एआई के साथ अकादमिक और अनुसंधान अखंडता, शोध में एआई का उपयोग, पेपर डेवलपमेंट वर्कशॉप (पीडीडब्ल्यू), प्रस्तुतियाँ आदि पर विभिन्न अत्यधिक जानकारीपूर्ण सत्र और कार्यशालाएँ शामिल थीं। कार्यक्रम का समापन स्वस्तिवचनिक सत्र (वैलेडिक्टरी) के साथ हुआ, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुधीर राणा ने समापन भाषण दिया। सत्र का समापन डॉ. आरती चंदानी, एफपीएम–चेयर द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के साथ हुआ।

एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता मे अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। शुक्रवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्त योजनान्तर्गत जनपद स्तर गठित समिति अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन हुई।बैठक में जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा कक्षा 11–12 स्तर पर प्रोफाइल अपडेट किये जाने सम्बन्धी एवं कक्षा 11–12 के उपर की संस्थाओं के द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की प्रक्रिया एवं लम्बित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गयी।छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9–10, कक्षा 11–12 एवं उसके उपर की कक्षाओ में छात्रछात्राओं द्वारा लगातार आवेदन किया जा रहा है, परन्तु शिक्षण संस्थानों के स्तर पर उन आवेदन पत्रों को अग्रसारित नही किया जा रहा है जिसके कारण काफी अधिक संख्या में आनलाइन आवेदन पत्र लम्बित पड़े है।बैठक मे अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान अपने स्तर आनलाइन आवेदन पत्रों को लम्बित न छोडे। उनके सापेक्ष नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ससमय अग्रसारितधनिरस्त करना सुनिश्चित करें। उक्त योजना सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हैं। जिसके सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया कि सभी शिक्षण संस्थाए अपने पोर्टल पर लम्बित ऑनलाइन आवेदन पत्रों की समीक्षा तत्काल करते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित करे। जिससे कि सीएम डैश बोर्ड पर रैकिंग नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। जनपद में उक्त योजनान्तर्गत सभी पात्र छात्रछात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन कराने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिक्षण संस्थाओं के कक्षाध्यापक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये एवं इसके सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था के प्रमुख द्वारा उनसे प्राप्त किया जाय। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद में स्थिति राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, आई०टी०आई० एवं पालीटेक्निक संस्थानो के प्रतिनिधि एवं अन्य सभी सम्बन्धित संस्थानो के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

17660 घन फिट पत्थरों से बन रहा शेषावतार मंदिर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर शेषावतार का भी मंदिर बनाया जा रहा है, जिसकी नींव के कार्य को पूरा कर पत्थरों से निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को शेषावतार, सप्त मंडपम और कुबेर टीला पर भगवान शिव के भी दर्शन कराए जाएंगे।राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे सप्त मंडप और शेषवतार मंदिर के निर्माण का कार्य सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे मंदिर को बनाने के लिए 17660 घन फिट पत्थरों का उपयोग किया जाना है, जिसकी भव्यता भी राम मंदिर से काम नहीं होगी। इसके साथ ही इन सभी मंदिरों को जोड़ने वाले दर्शन पथ को सही तरीके से तैयार किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालु आसानी से सभी मंदिरों तक जा सकें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में 18 मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है। धीरे–धीरे एक–एक मंदिर के कार्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि शेषावतार मंदिर का कार्य भी चल रहा है। इसके साथ ही चार महर्षियों के मंदिर निर्माणाधीन है जो तिथियां निर्धारित की गई है उसी तिथि पर पूर्ण होगा।

जयसिंहपुर एसडीएम संतोष कुमार ओझा सस्पेंड

ब्यूरो चीफ सुलतानपुर

सुल्तानपुर । जयसिंहपुर एसडीएम संतोष कुमार ओझा सस्पेंड।भ्रष्टाचार के मामले में शासन से हुई कार्यवाही,करीब 10 दिन पूर्व एसडीएम के पेशकर को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ घूस लेते किया था गिरफ्तार।हफ्ते भर पूर्व सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सस्पेंशन के दिए थे आदेश।गुरुवार की रात शासन ने भेजा जिला प्रशासन को सस्पेंशन लेटर।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठक सम्पन्न

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से गुरुवार को विधानपरिषद सभाकक्ष संख्या–80 में राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एस.एल.क्यू.ए.सी.) की पहली बैठक आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी और प्रदेश के उच्च शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नई नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार करते हुए नैक मूल्यांकन और एनआईआरएफ रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु वार्षिक योजना बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारिणी निकाय के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रकोष्ठ की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं, ताकि शिक्षा क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और नए शिक्षकों को ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। शैक्षणिक सत्र 2025–26 से राज्य के कॉलेजों के शोध प्रस्तावों को ष्समर्थ पोर्टलष के माध्यम से संचालित करने की योजना बनाई गई। इसके लिए समयबद्ध कार्य योजना और टाइमलाइन जारी करने पर भी सहमति बनी। साथ ही, प्रदेश में एकल प्रवेश प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया,।

जेसीपी एलओ दफ्तर से सरकारी बाइक हुई चोरी

लखनऊ,(संवाददाता)। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था (एलओ) के दफ्तर से चोर एक सिपाही की सरकारी बाइक चोरी कर ले गया। सिपाही ने नौ दिसंबर को वजीरगंज थाने में केस दर्ज कराया है। रिवर बैंक कॉलोनी में जेसीपी एलओ अमित कुमार का दफ्तर है। इसमें तैनात हेड कांस्टेबल अजय कुमार तैनात के मुताबिक बाइक (यूपी 32 बीजी 7758) कार्यालय से अटैच है। इसका इस्तेमाल कार्यालय से जाने वाली डाक के वितरण में होता है। आठ दिसंबर को दफ्तर की पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी हो गई। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।

दुकान के विवाद में बड़े भाई की गर्दन पर मारी आरी

लखनऊ,(संवाददाता)। सरोजनीनगर इलाके में दुकान के विवाद में बुधवार शाम युवक ने बड़े भाई की गर्दन पर आरी से हमला कर दिया। हमले में घायल बड़े भाई को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के अनुसार बिजनौर के रहीमाबाद इलाके में राजकिशोर रहते हैं। उनके बड़े भाई प्रदीप कुमार (40) सरोजनीनगर के शांति नगर इलाके में परिवार संग रहते हैं। दोनों की शांति नगर में पैतृक दुकान है, जो कुछ समय से बंद है। दुकान के लिए चल रहे विवाद के चलते दोनों ने अपना–अपना ताला दुकान पर लगा रखा है। शाम करीब पांच बजे प्रदीप दुकान के बाहर पहुंचे और वहीं बैठ गए। एक घंटे के बाद वह दुकान का ताला तोड़ने लगे। खबर पाकर राजकिशोर भी आ गए। कहासुनी के बाद राजकिशोर ने पास में पड़ी आरी उठाकर प्रदीप की गर्दन पर वार कर दिया। खून से लथपथ होकर प्रदीप गिर पड़े और राजकिशोर भाग गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है।

150 साल पहले की ग्रामीण सभ्यता की होगी पहचान

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय के पुरातात्विक सर्वेक्षण में 150 साल पहले की ग्रामीण सभ्यता की पहचान सामने आएगी। सर्वेक्षण में पहली बार रिमोट तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा सेटेलाइट के जरिये सर्वे स्थल का मानचित्र तैयार किया जाएगा। निदेशालय की तरफ से जनवरी में पांच जिलों में ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत की जाएगी। निदेशालय के अनुसार, जिन क्षेत्रों का सर्वे किया जाना है, वहां अलग–अलग शासन काल के छोटे–छोटे स्मारक भी हैं। सर्वेक्षण के बाद उन स्मारकों को संरक्षित किया जाएगा। राज्य पुरातत्व निदेशक रेनू द्विवेदी ने बताया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण के लिए शासन से अनुमति भी मिल गई है। गोंडा जिले के बेलसर में ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा कौशांबी के सदर तहसील में, जौनपुर के शाहगंज तहसील में, हमीरपुर के मौदहा तहसील में और मैनपुरी के कुरावली में भी सर्वेक्षण किया जाएगा।

छह परिचालकों को हटाया, एजेंसी से मांगा नया स्टॉफ

लखनऊ,(संवाददाता)। आउटसोर्सिंग से रायबरेली डिपो में काम कर रहे छह परिचालकों की छुट्टी कर दी गई है। काफी समय से बिना सूचना के गैरहाजिर रहने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने परिचालकों को वापस कर एजेंसी को नए परिचालक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रायबरेली डिपो में आउटसोर्सिंग के परिचालक रामकुमार, मनोज अवस्थी, अंकित शुक्ला, राहुल मिश्रा, नीतू सिंह व पंकज कुमार लंबे समय से बिना सूचना के गैरहाजिर थे। कई बार निर्देश देने के बाद भी वे काम पर वापस नहीं लौटे। दो दिन पहले संबंधितों को अंतिम नोटिस जारी की गई, जिसका भी जवाब नहीं दिया। बुधवार को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने छह परिचालकों को हटाते हुए संबंधित एजेंसी को वापस कर दिया। बताया कि नए परिचालकों की व्यवस्था की जाएगी।

बच्चे को लेकर भाग निकला मानव तस्करी का आरोपी

लखनऊ,(संवाददाता)। मानव तस्करी के मामले में कानपुर पुलिस ने बुधवार सुबह आलमबाग में छापा मारा। हालांकि इससे पहले ही आरोपी सुनील मलिक भाग निकला। घर पर कोई भी नहीं था। नाबालिग भी पुलिस को नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस की कार्रवाई की खबर सुनील को लग गई थी। मंगलवार को ही आरोपी बच्चे को लेकर कहीं चला गया। कानपुर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इंस्पेक्टर आलमबाग के मुताबिक पुलिस टीम सुबह आठ बजे लखनऊ आई थी। स्थानीय पुलिस के साथ टीम ने सुनील के घर पर दबिश दी, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। सुनील की तलाश की जा रही है। आस पड़ोस के लोगों ने पूछताछ में बताया कि सुनील कुछ माह पहले दो बच्चों को लेकर आया था। इसमें एक बच्चा उसने अपनी बेटी के घर कानपुर भेज दिया था, जबकि दूसरा सुनील के घर पर काम करता था। पुलिस बच्चों के पिता से संपर्क कर रही है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को गुरुग्राम से श्रीभगवान नामक व्यक्ति ने कानपुर पुलिस को कॉल कर बेटे को बचाने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने गोविंदनगर बी–ब्लॉक निवासी फर्नीचर कारोबारी अंकित आनंद के घर छापा मारा था। इस दौरान अंकित के घर से 12 साल का बालक बरामद किया गया था। बालक से अंकित और उसके घरवाले शौचालय की सफाई कराते थे। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। पूछताछ में अंकित ने बताया था कि आलमबाग निवासी ससुर सुनील मलिक ने गुरुग्राम निवासी दलाल पप्पू यादव के जरिये बिहार के पूर्वी चंपारन जिले के तरनियाघाट निवासी श्रीभगवान महतो उर्फ रामू से 12 व 8 साल के बच्चों को 30–30 हजार रुपये में खरीदा था। कानपुर पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुनील की तलाश जारी है।

परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम मौका

लखनऊ,(संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने से चूके विद्यार्थियों के पास बृहस्पतिवार को फॉर्म भरने का अंतिम मौका है। छात्र–छात्राओं के अनुरोध पर परीक्षा विभाग ने तिथि विस्तारित कर दी है। इसके बाद फॉर्म भरे जाने की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। लविवि में 17 दिसंबर से सभी कोर्सों के लिए पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसमें शामिल होने के लिए 25 नवंबर से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर तय की गई थी। इसके बावजूद तकनीकी खामी और निजी समस्याओं के चलते हजारों छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। इसके लिए उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था जिस पर विचार करते हुए उन्होंने दो दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को परीक्षा भरने फॉर्म का पोर्टल दोबारा खोल दिया। मालूम हो कि लविवि से संबद्ध जिलों हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के सहयुक्त कॉलेजों में तीन लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। स्नातक विषम सेमेस्टर के सभी कोर्स के लिए अगले दो से तीन दिनों में प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

फाफामऊमें ब्लॉक से छह ट्रेनें रहीं निरस्त

लखनऊ,(संवाददाता)। फाफामऊ और प्रयागराज में रेल लाइनों पर चल रहे काम की वजह से बुधवार को मेगा ब्लॉक लिया गया। इससे छह ट्रेनें निरस्त रहीं। ऊंचाहार एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से चलाई गई, जिससे यह ट्रेन भी नहीं आई। पहले से कोई जानकारी न होने पर यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई। ऊंचाहार ही नहीं, लालगंज, डलमऊ व अन्य रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे यात्रियों को निराश होकर लौटना पड़ा। प्रयागराज संगम में महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रेलवे भी नए कार्य कराने के साथ ही पुराने कार्यों की मरम्मत कराकर उन्हें दुरुस्त करा रहा है। फाफामऊ और जंघई रेलवे स्टेशनों के बीच पुलिया निर्माण के लिए फाफामऊ से प्रयाग और जंघई जाने वाली रेल लाइनों पर ट्रैफिक ब्लॉक एवं पॉवर ब्लॉक लिया गया। इस वजह से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। इस दरम्यान गुजरने वाली छह ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया तो एक ट्रेन बदले हुए मार्ग से चलाई गई। सुबह कानपुर–प्रयागराज पैसेंजर, कानपुर–प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस और लखनऊ–प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त होने के कारण नहीं आई। इसीलिए शाम को प्रयागराज–कानपुर पैसेंजर, प्रयागराज–कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और प्रयागराज–लखनऊ इंटरसिटी भी रद्द रही। चंडीगढ़ से प्रयागराज जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस का रूट डायवर्जन किया गया, जिससे इन ट्रेन ने कानपुर से रास्ता बदल लिया और दूसरे मार्ग से प्रयागराज पहुंच गई। इससे लालगंज, डलमऊ, ऊंचाहार समेत अन्य स्टेशनों पर नहीं आई। ट्रेनों के निरस्त होने या रूट डायवर्जन की जानकारी पहले से नहीं थी, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। रेलवे स्टेशनों पर काफी इंतजार के बाद ट्रेन के निरस्त होने का पता चला तो घरों को लौट गए या फिर रोडवेज बसों और दूसरे वाहनों का सहारा लिया। यात्री गुलजार अहमद, सुकेश सिंह, मंजू, जवाहर लाल, राधेश्याम, संगीता देवी, सुषमा सिंह, शैलजा, कुलदीप तिवारी ने बताया कि पहले से जानकारी हो जाती तो इतनी परेशानी न होती। स्टेशन अधीक्षक विनोद त्रिपाठी ने बताया कि मेगा ब्लाक के चलते ट्रेनें निरस्त रहीं।

दिल की बीमारी से किशोर की मौत

लखनऊ,(संवाददाता)। तापमान में गिरावट आना शुरू हो गई है। ठंड मरीजों को झटका दे रही है। चपेट में बच्चे और किशोर ज्यादा आ रहे हैं। ठंड के कारण दिल की समस्या होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किशोर की मौत हो गई। बुधवार को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे बुखार, डायरिया व अन्य बीमारियों के 10 बच्चों समेत 17 मरीजों को भर्ती किया गया। बुखार से हालत बिगड़ने के बाद भर्ती बुजुर्ग की मौत हो गई। भदोखर क्षेत्र के पकरा गिरिफ्ता निवासी राजन (16) पुत्र रमई को दिल और फेफड़े में दिक्कत होने के बाद बीती चार दिसंबर को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कई दिनों तक इलाज के बाद बुधवार को किशोर की मौत हो गई। इसके अलावा हरचंदपुर क्षेत्र के पूरे लखन निवासी राम अभिलाष (76) की भी मौत हो गई। राम अभिलाष को बुखार सहित अन्य समस्या के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को बुखार व डायरिया के चपेट में आने के बाद अमल (12), शुभम (10), आयुष (1), सृष्टि (6), अबी (9), एकता (3), राखी (10), सुमन (12), श्रेया (5), आदर्श (11) समेत 17 मरीजों को भर्ती कराया गया। बुधवार को को ओपीडी में भी 1900 से अधिक मरीज विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने पहुंचे। मेडिसन विभाग की ओपीडी पांच सौ से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे। सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार व सांस की समस्या वाले रहे। करीब 20 से 25 मरीज सीने में परेशानी वाले पहुंचे। ठंड बढ़ने के बाद मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. गौरव त्रिवेदी का कहना है कि सर्दी में रक्त वाहिनियों संकरी हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर सामान्य से कुछ ज्यादा रहता है, जो मरीजों के लिए परेशानी की वजह बनता है। ऐसे रोगियों को घबराहट, हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द, जकड़न, सांस फूलना, अचानक पसीना आना और फिर ठंड लगने की दिक्कत होती है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तत्काल चिकित्सक की सलाह के अनुसार इलाज कराएं। ठंड को देखते दिल के मरीजों को विशेष सावधानी की जरूरत होती है। नियमित अपनी दवाओं का सेवन करें। समय–समय पर चेकअप कराएं। सुबह और शाम के समय से बाहर निकलने से बचें। बताया कि इमरजेंसी के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है।

निजीकरण विरोधी दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी, कहा-पावर कार्पोरेशन प्रबंधन बना रहा औद्योगिक अशांति का माहौल

लखनऊ,(संवाददाता)। यूपी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी और अभियंता 13 दिसंबर को निजीकरण विरोधी दिवस मनाएंगे। कार्यालय समय के उपरांत समस्त जनपदों, परियोजनाओं एवं राजधानी लखनऊ में सभा करेंगे। संघर्ष समिति का आरोप है कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन अनावश्यक तौर पर निजीकरण का निर्णय लेकर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया है। बिजली कर्मचारी शांतिपूर्वक बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने में लगे हुए थे, लेकिन अब प्रबंधन इसे पटरी से उतार देने पर तुला हुआ है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय,सुहैल आबिद, पीके दीक्षित, राजेंद्र घिल्डियाल आदि ने संयुक्त बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के रहते हुए सबसे ज्यादा सुधार बिजली व्यवस्था में हो रहा है। बिजली कर्मचारी और अभियंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था के सुधार में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने अचानक प्रदेश के 42 जनपदों में बिजली वितरण के निजीकरण की घोषणा कर बिजली कर्मियों को उद्वेलित कर दिया है। अनावश्यक रूप से ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया है । बिजली कर्मी अभी भी पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और निजीकरण के विरोध में सभी ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कार्यालय समय के उपरांत कर रहे हैं, जिससे बिजली व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से वर्ष 2023– 24 में प्रति यूनिट 4.47 रुपया मिल रहा है जबकि निजी क्षेत्र की टोरेंट कंपनी से आगरा शहर में

पावर कारपोरेशन को मात्र 4.36 रुपए प्रति यूनिट मिला है। यह आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं की ग्रामीण क्षेत्र और चंबल के बीहड़ रहते हुए भी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से पावर कारपोरेशन को अधिक पैसा मिल रहा है। टोरेंट को बिजली देने में पावर कारपोरेशन को घाटा हो रहा है ।फिर भी निजीकरण के ऐसे विफल प्रयोग को पावर कार्पोरेशन प्रबंधन किस कारण से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर थोपना चाहता है।। समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की अरबों रुपए की बेशक कीमती जमीन किस आधार पर मात्र एक रुपए में निजी घरानों को सौंप दी जाएंगी। यह जनता की परिसंपत्ति है। इसके अतिरिक्त अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियों और कार्यालयों को बिना परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किए किस आधार पर और कितने रुपए में निजी कंपनी को बेचने की तैयारी है ? इन सब बातों से बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता बहुत अधिक परेशान और उद्वेलित है। इसीलिए शांति पूर्ण ढंग से ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में कांग्रेस

लखनऊ,(संवाददाता)। यूपी में कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में है। सदन में सिर्फ दो विधायक वाली कांग्रेस ने नई रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को 18 दिसंबर को लखनऊ आने का आह्वान किया है। इस दिन वह विधानसभा भवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को प्रेसवार्ता में कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर तबाही और हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर फर्जी दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर एनकाउंटर किया जा रहा है। महिलाओं से दुर्व्यवहार हो रहा है। अराजकता बढ़ती जा रही है। कहा कि इसके बाद भी सरकार चुप है। सरकार के इशारे पर पुलिसकर्मी ही उत्पीड़न करने में लगे हैं। इसके विरोध विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा किविपक्ष के सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाले विधानसभा घेराव में सहयोग करें। लोकल की जगह गुजरात के लोगों को दिया जा रहा काम उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। जो काम पहले लोकल ठेकेदारों को दिया जाता था, वह अब गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुजरात की कंपनियों में पूरा एकाधिकार कर रखा है। ऐसे में काम की गुणवत्ता प्रभावित होना सभाविक है। क्योंकि, यह कंपनी यहां किसी भी तरह से काम करके लौट जाएंगी। फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। इस दौरान विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आज हर विषय पर असफल हो चुकी है। चाहे वह किसान का मुद्दा हो। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो। विधानसभा के अंदर इन सवालों का जवाब भाजपा नहीं दे रही है। वह किसी भी चीज का जवाब देने को तैयार नहीं है। कहा कि इसलिए एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार की जवाबदेही उन विषयों पर ली जाए, जिस पर जनता ने उनका विश्वास कर जनता ने उनको विधानसभा में भेजा है।। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सदन में हमारी सख्या कम है तो हम सदन के बाहर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले सपा को लगेगा बड़ा झटका

लखनऊ,(संवाददाता)। क्या यूपी में आम विधानसभा चुनाव से पहले जेल में बंद सपा महासचिव आजम खां अलग राह पकड़ सकते हैं? उनके नजदीकी नेता बताते हैं कि रामपुर के मामले में इंडिया गठबंधन पर निशाना साध आजम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही संदेश देने का काम किया है। जिस तरह से रामपुर में लोकसभा का टिकट पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम की बिना मर्जी के दिया गया और संभल के सांसद पर एफआईआर को सपा ने प्रमुखता दी, उससे कहीं न कहीं आजम को मुसलमानों को बीच अपनी सियासी जमीन भी खिसकती दिखाई दे रही है। संभल पर सपा और कांग्रेस के बीच सियासी दरार पड़ती नजर आ रही है तो जेल में सजा काट रहे आजम खां ने इंडिया गठबंधन को कठघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने आजम के सियासी संदेश को पत्र के जरिये लोगों के सामने रखा है। आजम के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। कहा है कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुस्लिमों को भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम ने यह भी कहा कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए, जितना संभल का मुद्दा उठाया गया। रामपुर के जुल्म और बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोशी तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। सपा के रामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और आजम के बेहद करीबी माने जाने वाले वीरेंद्र गोयल कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं से भी मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि आजम का दर्द सामने आया है। यहां बता दें कि लोकसभा चुनाव में आजम चाहते थे कि रामपुर से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ें। आजम वहां किसी मुस्लिम नेता को पैर जमाने देना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे लेकिन सपा ने वहां से मोहिब्बुल्लाह को टिकट दिया और वे जीत भी गए। सपा सूत्र बताते हैं कि रामपुर के लोकसभा टिकट ने आजम की सपा नेतृत्व से दूरियां बढ़ाईं।

आजम को यह भी महसूस हो रहा है कि उनके मामले को सड़क से संसद तक उतनी प्रमुखता से नहीं उठाया गया, जितनी संभल के प्रकरण को तरजीह दी गई।

इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर का छापा

लखनऊ,(संवाददाता)। यूपी में आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के आधा दर्जन शहरों के 25 ठिकानों पर छापा मारा है। राजधानी में कंपनी के ऐशबाग स्थित वाटर वर्क्स रोड पर कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय को खंगाला जा रहा है। इसी तरह नोएडा, मुंबई, बरेली और हरदोई में भी छापे मारे गए हैं। कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने की शिकायतों के बाद आयकर विभाग ने यह कदम उठाया है। सूत्रों की मानें तो इंडियन पेस्टिसाइट लिमिटेड द्वारा बीते कई वर्षों के आयकर विवरण में तमाम अनियमितताएं मिल रही थीं। जिसके बाद इस मामले की जांच का जिम्मा इंवेस्टिगेशन विंग को सौंपी गई, ।

आईटीआई में रोजगार मेला 19 व 21 को

लखनऊ,(संवाददाता)। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की प्लेसमेंट अधिकारी प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया कि 19 दिसंबर को श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कॉर्पोरेट कंपनी में प्रोडक्शन, ऑपरेटर व अन्य 250 पदों पर भर्ती होगी। इंटरमीडिएट और आईटीआई पास युवा कैंपस प्लेसमेंट में प्रतिभाग कर सकेंगे। चयन होने पर प्रति माह 15 हजार रुपये वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसी तरह 21 दिसंबर को भी रोजगार रोजगार मेला लगेगा। यहां आने वाली कंपनियों की सूची जल्द जारी की जाएगी।

फरार सचिव के खिलाफ आठ माह बाद गबन का केस दर्ज

लखनऊ,(संवाददाता)। साधन सहकारी समिति नसीराबाद के सचिव ने खाद की बिक्री में 14 लाख रुपये का गबन किया। फरार चल रहे सचिव के खिलाफ आठ माह बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते हैं कि थाना क्षेत्र के चतुरपुर निवासी रामकेवल पाल साधन सहकारी समिति नसीराबाद में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आठ माह पहले यहां 14 लाख रुपये का गबन का मामला सामने आया था। इस पर सचिव को नोटिस देकर निलंबित कर दिया गया था। गबन की घटना के बाद सचिव फरार हो गया। अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील प्रभारी प्रवीण मिश्रा की तहरीर पर सचिव के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक आयुष वत्स को सौंपी गई है। साधन सहकारी समिति नसीराबाद में 14 लाख रुपये का गबन होने के बाद खाद नहीं आ रही है। ऐसे में समिति से जुड़े आलमपुर, बेढौना, बेंहटा, महमदपुर, बोझी, भूलामऊ व नसीराबाद कस्बे के लगभग दस हजार किसानों को खाद के लिए दूसरी समितियों व बाजार में महंगे दामों पर दाम लेनी पड़ रही है। सचिव रामकेवल पाल की पत्नी ईश्वर देई का कहना है कि 14 लाख रुपये गबन का मामले में पति के खिलाफ विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन इस गबन में अकेले मेरे पति शामिल नहीं है। समिति के आंकिक व जिला सहकारी बैंक नसीराबाद के शाखा प्रबंधक भी आरोपी है। आरोप लगाया कि सचिव की आईडी से समिति का आंकिक भी किसानों को खाद देता था। इनकी भी जांच होनी चाहिए।थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि सभी तथ्यों को लेकर जांच की जाएगी।

पत्नी से विवाह करने पर चचेरे भाई पर पेट्रोल डाला

लखनऊ,(संवाददाता)। पत्नी से कोर्ट मैरिज करने पर नाराज आरोपी ने चचेरे भाई पर पेट्रोल डाल दिया। इससे वह धू–धू कर जलने लगा। परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई। चचेरा भाई करीब 45 फीसदी झुलस गया। सीएचसी से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के अत्तानगर गांव निवासी मातादीन (55) पुत्र भवानी प्रसाद मंगलवार शाम करीब सात बजे दरवाजे पर देर शाम अलाव ताप रहे थे। तभी गुस्साए गुलाब प्रजापति ने उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से भाग गया। आग की लपटों से घिरा मातादीन चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर घर के बगल उनकी भाभी फूलमती समेत गांव के अन्य लोगों ने आग को बुझाया। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर आई पुलिस ने मातादीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी जेपी सिंह के मुताबिक आरोपी गुलाब और उसकी पत्नी रामावती के बीच अनबन चल रही थी। करीब 10 साल पहले मातादीन ने गुलाब की पत्नी रामावती से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात को लेकर गुलाब उससे खुन्नस रखता था। मातादीन की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पहली पत्नी से मातादीन के छह बेटियां हैं। इनमें चार बेटियों की शादी के बाद अपनी दो बेटियों व दूसरी पत्नी की दो बेटियों के साथ वह मुंबई चला गया था। वहां ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। बीती 11 नवंबर को वह अपने घर का निर्माण कराने के लिए गांव आए थे। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अमित सिंह ने बताया कि मातादीन 40 से 45 प्रतिशत झुलसे थे। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मातादीन की तहरीर पर गुलाब के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

खराब ट्रैफिक सिग्नल ने बिगाड़ी राजधानी की यातायात व्यवस्था

लखनऊ,(संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को कमता चौराहे के खराब ट्रैफिक सिग्नल ने लोगों को जाम के झाम में डाल दिया। घंटों तक लोग लाइन में खड़े रहे। व्यवस्था सुधारने में ठंड में भी पुलिसकर्मियों ने पसीना छोड़ दिया। करीब एक किमी से भी लंबा जाम लगा

रहा। दरअसल दो दिन पहले शहीद पथ पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की फ्लीट हादसे की शिकार हो गई थी। इसके चलते रूट डायवर्जन लगाया गया। ऑटो और छोटे बार वाहनों को शहीद पथ पर एंट्री नहीं दी गई। इन्हें सर्विस लेन से आगे जाने के लिए कहा गया। इस वजह से पॉलिटेक्निक चौराहे से अयोध्या जाने के लिए हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया। उधर कमता चौराहे की सिग्नल लाइट खराब हो गई। नतीजा यह हुआ कि कमता चौराहे पर वाहनों की कतार लगनी शुरू हुई तो करीब किमी तक लंबी लाइन लग गई। लोग जाम में परेशान दिखे। किसी को अस्पताल जाने में तो किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में घंटों की देरी का सामना करना पड़ा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।